प्रसंगवश :

आलोक मेहता

आसान नहीं डॉक्टर की राह

आमिर खान ने 'सत्यमेव जयते' कार्यक्रम में डॉक्टर बिरादरी के एक बेईमान समूह का पर्दाफाश कर अच्छा काम किया। तालियां बजीं। टी.वी. चैनल की रेटिंग के साथ विज्ञापन की दरें भी अच्छी हो गईं। निजी चैनल स्टार प्लस के साथ पब्लिक ब्रॉडकास्टर दूरदर्शन भी इस शृंखला को प्रसारित कर रहा है। लेकिन 'पब्लिक' की प्रतिनिधि सरकार में बैठे स्वास्थ्य मंत्री या उनके अफसर सलाहकारों पर कोई असर होगा? कतई नहीं। उनके दफ्तर में इस कार्यक्रम से कई हजार गुना पत्र, ज्ञापन, जांच रिपोर्ट, कार्रवाई की सिफारिशें पड़ी हुई हैं लेकिन उदार अर्थव्यवस्था की ताकत वाली चिकित्सा तथा दवाई निर्माता क्षेत्र में किसी भी लोकप्रिय अभिनेता, चैनल, ईमानदार सांसद या सामाजिक संस्थाओं से अधिक ताकतवर है। उदारीकरण के प्रारंभिक दौर यानी नरसिंह राव के प्रधानमंत्री रहते देश के पहले बड़े निजी अस्पताल समूह को राजधानी दिल्ली में विशालकाय अस्पताल के लिए करोड़ों रुपयों की जमीन मात्र एक रुपए में दी गई थी। अब यह बहुराष्ट्रीय कंपनी का अस्पताल समूह बन चुका है। उस समय सत्ता व्यवस्था में शक्तिशाली एक कुख्यात तांत्रिक ने इस समूह को आशीर्वाद दे रखा था और विदेशों के लिए भी दलाली की थी। इस कंपनी के अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टरों की फीस का 60 प्रतिशत हिस्सा कंपनी को देना होता है। सामान्य चेक-अप के 25 से 50 हजार रुपए देने के बाद 'ग्राहक' देखकर यथासंभव ऑपरेशन की सलाह दी जाती है और 'फाइव स्टार आई.सी.यू.' में 10 दिन बाद मृत्यु हो जाने पर भी 10-20 लाख रुपया चुकाए बिना मृत शरीर बाहर ले जाने की अनुमति नहीं मिलती है। ऐसे 'फाइव स्टार समूह' पर सरकार सर्वाधिक मेहरबान है, क्योंकि वहां सत्ता या प्रतिपक्ष के प्रभावशाली नेताओं-अफसरों आदि का इलाज 'गरीब' कोटे में मुफ्त होता है। इसी तरह कुछ बड़े पूंजीपति 'धर्मार्थ चिकित्सालय' और 'अनुसंधान केंद्र' के नाम पर अस्पताल खोलकर अपने परिजनों और सत्ताधारियों को मुफ्त चिकित्सा तथा बाहरी 'ग्राहकों' से करोड़ों का मुनाफा कमा लेते हैं। 'धर्मार्थ' तथा 'अनुसंधान' की कागजी कार्यवाही एवं तख्ती से देसी-विदेशी मशीनों-उपकरणों पर टैक्स-एक्साइज ड्यूटी में पूरी छूट मिल जाती है। ऐसे अस्पतालों में नौकरी या कंसलटेंसी करने वाले डॉक्टरों को 'सेवा' के नाम पर गुलामी के अलावा और क्या मिलता है?

ऐसा नहीं है कि पहले किसी न्यूज टी.वी. चैनल या अखबार ने 'चिकित्सा सेवा' के नाम पर हो रहे काले धंधे का पर्दाफाश नहीं किया। हां, आमिर खान का नाम बड़ा होने से उस पर जनता का ध्यान अधिक गया होगा। यह बात अलग है कि आमिर खान के कार्यक्रम के अतिथि मेडिकल काउंसिल के अध्यक्ष भी अफसोस के साथ सारी बुराइयों को स्वीकारते हुए चले गए। उन्होंने खुद अपने दफ्तर में उपलब्ध दस्तावेजों का उल्लेख नहीं किया। आखिरकार, उन्हें अपनी बिरादरी और सरकार की खुशी-नाराजगी का भी ध्यान रखना है। सत्ता में स्वास्थ्य मंत्रालय को महत्वपूर्ण नहीं माना जाता। मंत्री नीतियों के बजाय एम्स में किसी की भर्ती की सिफारिश या मेडिकल कॉलेज की मान्यता पर अधिक ध्यान देते हैं। भाषण कितने ही देते हों, उन्हें ईमानदार और योग्य डॉक्टर तैयार करने, संरक्षण देने तथा सरकारी अस्पतालों में अधिक वेतन-सुविधाएं देने और दवाई-उपकरण लगाने की अधिक चिंता नहीं रहती। इस सबके लिए महीनों-वर्षों तक फाइलें घूमती रहती हैं। सबसे कॉम्प्लिकेटेड बात यह है कि शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र का

एक दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह व गुलाम नबी आजाद

कामकाज संघीय ढांचे में राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में है। उदार केंद्र सरकार अरबों रुपया राज्यों को पहुंचा भी दे तो उत्तर प्रदेश की तरह विभिन्न राज्यों के नेता और अफसर चिकित्सा तथा दवाई के खाते में ही करोड़ों रुपया डकार जाते हैं।

स्वास्थ्य सेवाओं की गड़बड़ियों पर किताबें लिखी जा सकती हैं लेकिन आमिर खान सहित उद्धारक, मीडियाकर्मी और संवेदनशील जनप्रतिनिधि सचमुच ईमानदारी और निष्ठा से जनता को स्वास्थ्य सेवा देने की इच्छा रखने वाले डॉक्टरों की ओर भी देश-दुनिया का ध्यान क्यों नहीं दिलाते? नक्सलियों के साथ सहानुभूति रखने वाले डॉक्टर विनायक सेन के लिए दिल्ली से लंदन-बर्लिन तक समर्थन मिल जाता है लेकिन ओडिशा, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों, आंध्र, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान में कार्यरत सैकड़ों निष्ठावान डॉक्टरों की सहायता के लिए कोई अभियान नहीं चलाया जाता। उनकी आमदनी और सुविधाएं न्यूनतम होती हैं। अब मेडिकल पढ़ाई के बाद गांवों में जाने की अनिवार्यता पर जोर दिया जा रहा है। यह निश्चित रूप से जरूरी है लेकिन गांवों में पहले से सेवा करने वाले डॉक्टरों के लिए छोटा-सा चिकित्सा केंद्र बनाने की व्यवस्था भी तो की जाए। इन डॉक्टरों के लिए वाहन, मकान की सुविधाएं तो दी जाएं। नक्सली-माओवादी समर्थक गरीबों को चिकित्सा-शिक्षा की सुविधाएं न होने पर आक्रोश व्यक्त करते हैं लेकिन बिना सड़क और गाड़ी के डॉक्टर वहां काम कैसे करेंगे? डॉक्टरों की सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले डॉक्टरों को आई.ए.एस. अफसर के समान वेतन और सुविधाएं क्यों नहीं दी जा सकतीं? दूसरी तरफ दिल्ली-मुंबई जैसे महानगरों में सरकारी अस्पतालों की सुविधाएं सीमित हैं और सामान्य निजी चिकित्सक भी 104 डिग्री बुखार या किसी गंभीर बीमारी से प्रभावित मरीज को देखने के लिए घर जाने को तैयार नहीं होते। मतलब, दो धाराएं समानांतर चल रही हैं। अच्छे समर्पित डॉक्टरों को समुचित सम्मान, वेतन, सुविधाएं नहीं मिलतीं और धंधेबाज लूट में लगे हुए हैं। इस स्थिति में बदलाव के लिए सत्ता और समाज को बड़ी इच्छाशक्ति के साथ काम करना होगा।

alokmehta@nationalduniya.com